Admission to Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi

2307. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that since the grant of autonomy to Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, in 1972 and deemed University status in 1986; the admission of students to the Under-graduate courses has been done without any rules being framed;

(b) whether the reservation policy of Government is not being followed in the admission of students in the Institute; and

(c) if so what steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) The admission of students of the Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi is made on the basis of merit in an all India entrance examination conducted by the Institute comprising a written test followed by interview. The written test is taken in four papers, Physics, Chemistry, Mathematics/Biology and English. The test is held at selected centres all over the country. This is in accordance with the admission policy and procedure framed by the Institute.

(b) Seats for SC/ST candidates are reserved by the Institute in accordance with Government of India norms (15 per cent for SC and 7-1/2 per cent for ST candidates).

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

2308. **श्री शरद यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) सरकार ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अब तक क्या-क्या प्रयास किये हैं ;

(ग) प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि उक्त सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) और (ग) जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसके अंतर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे । बाद के चरण में इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे । 1980-81 से 1987-88 तक वर्षवार लक्ष्य और नामांकन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये) ।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं और राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम को आवश्यक रूप से कार्यान्वित किया गया था । अन्य योजनाएं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुदृढ़ किया, इस प्रकार थीं :—

1. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियो को सहायता की योजना ।
2. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना ।
3. विश्वविद्यालय और कालेजों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ।
4. केन्द्रीय प्रायोजित उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रौढ़ शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग बनाया गया था और प्रौढ़ निरक्षरता को भी बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया था । छठी योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र में 92.81 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है । सातवीं योजना में 130 करोड़ रुपये की लागत केन्द्रीय क्षेत्र में और 230 करोड़ रुपये की लागत राज्य क्षेत्र में निर्धारित की गई है ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन अनेक मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा साथ-साथ किया गया था, जिन्होंने इसकी मजबूती और कमजोरी दोनों का पता लगाया है । ये हैं :—

क्षेत्र पक्ष

1. महिलाओं का प्रोत्साहन और सहभागिता उच्च थी ।
2. अनु० जाति/अनु० जनजाति को लक्ष्यों से अधिक शामिल किया गया था ।
3. प्रबन्ध के प्रति परियोजना दृष्टिकोण व्यवहार्य है ।
4. राज्य संसाधन केन्द्रों ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके द्वारा प्रकाशित शिक्षण/अध्ययन सामग्री की कोटि अच्छी थी ।
5. उन राज्यों में इस कार्यक्रम ने अच्छा कार्य किया, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा कर्मचारियों की भर्ती विशेष चयन कार्यवाहियों के अंतर्गत की गई थी ।

समस्याएं

1. पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की कोटि निम्न थी ।
2. निरीक्षण पद्धति में विश्वसनीयता की कमी थी । पर्याप्त रूप से गलत जानकारी दी गई थी ।
3. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन-वातावरण निष्क्रिय था, बिजली की व्यवस्था खराब थी ।
4. जन संचार माध्यमों ने पर्याप्त सहयोग नहीं दिया ।
5. स्वैच्छिक एजेंसियों को राज्य सरकारों से सहयोग नहीं मिला और उनकी सहभागिता के लिए निर्धारित कार्यविधियों ने उन्हें हतोत्साहित किया ।
6. 'शिशुओं' की सहभागिता अनियमित थी और स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों और फिर से निरक्षर बनने वालों की पर्याप्त संख्या थी ।
7. साक्षरता-स्तर की उपलब्धि सामान्यतया आशा से कम थी और संचालनात्मकता के घटकों का वितरण और जागरूकता कमजोर रही ।
8. उत्तर-साक्षरता और सतत शिक्षा प्रबन्धों के अभाव से इस कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।
9. राज्य सरकारों और पंचायती राज्य संस्थाओं का राजनीतिक तथा प्रशासनिक सहयोग उपयुक्त और स्थायी ढंग से प्राप्त नहीं हो रहा था ।

विवरण

वर्ष	लक्ष्य	(लाखों में) नामांकन
	कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था	
1980–81	–वही–	25.91
1981–82	–वही–	30.99
1982–83	45.30	43.57
1983–84	51.06	51.48
1984–85	61.55	61.75
1985–86	75.46	66.53
1986–87	83.60	81.50
1987–88	89.23	80.69